कृषि निर्यात नीति 2018

संदर्भ

हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि यह मंजूरी किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से दी गई है। यह नीति कृषि निर्यात के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी जिसमें आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमों को सुव्यवस्थित करना, कृषि संकट को बढ़ावा देने वाले फैसलों को कम करना और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कृषि निर्यात नीति, 2018 का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक करना है।
- ध्यातव्य हो कि यह फैसला 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के उद्देश्यों के तहत लिया गया है।
- कृषि निर्यात नीति से चाय, कॉफी और चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ यह वैश्विक कृषि व्यापार में देश की हिस्सेदारी को बढ़ाएगी।
- इस नीति के तहत जैविक उत्पादों पर सभी प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों को भी हटाने की कोशिश की जाएगी। एक अधिकारी के मुताबिक, इस नीति के कार्यान्वयन के लिये अनुमानित वित्त 1,400 करोड़ रुपए से अधिक का होगा।

कृषि निर्यात नीति के अवयव

- कृषि निर्यात नीति में की गईं सिफारिशों को दो श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है।

- **सामरकि (Strategic)**

सामरकि श्रेणी में तहत नम्नलखिति उपाय शामलि होंगे-

♦ नीतगित उपाय
♦ अवसंरचना एवं रसद समर्थन
♦ नर्यात को बढ़ावा देने के लयि समग्र दृष्टकिोण
♦ कृषनिर्यात में राज्य सरकारों की बड़ी भागीदारी
♦ मूल्य वर्द्धति नर्यात को बढ़ावा देना
♦ 'ब्रांड इंडयि' का वपिणन और प्रचार

- **परचािलन (Operational)**

परचािलन के तहत नम्नलखिति कार्य शामलि होंगे-

♦ उत्पादन और प्रसंस्करण में नजिी नविश को आकर्षति करना
♦ मज़बूत नयिमों की स्थापना
♦ अनुसंधान एवं वकिास
♦ ववििधि

स्रोत- इंडयिन एक्सप्रेस, पीआईबी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/agriculture-export-policy-2018